आदिम जनजातियों की विकास के सुनहरे सपनों का हस्त्र

जसिन्ता केरकेट्टा

दिम जनजाति पहाड़ियाओं के लिए सरकार ओर से करोड़ों रूपये की राशि आवंटि त ी है। उनके रहने के लिए बिरसा आवास लेकर उनके स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण क की योजनाएं हैं। कई योजनाएं वर्तमान में न भी रही हैं लेकिन किसी न किसी पेंच के रण योजनाएं अधर में लटकी रहती हैं। वंटित राशि या तो निकासी नहीं हो पाती, कासी की गई तो लैप्स कर जाती हैं और कास के सुनहरे सपने हवा में तैरते रह जाते करोड़ों की राषियों के बाद भी विकास के हरे सपनों का हस्त्र बुरा है। दूसरी ओर ार पर चंद लोगों का ऐसा वर्चस्व है कि ड़िया चाहकर भी अपनी चीजें बाजार में कर स्वयं नहीं बेच सकते। इसके पीछे भी साजिश चलती है। साहेबगंज जिले की की दो छात्राएं सारा पहाड़िया व स्टेला ड़िया के चेहरे के रंग तब उड़ जाते हैं जब जिला कल्याण पदाधिकारी ललीता मिंज मुंह से यह सुनती हैं कि पहाड़िया बच्चों उच्च षिक्षा व प्रषिक्षण के लिए उनके पास योजना नहीं हैं। दोनों छात्राएं बार-बार ती हैं कि उन्होंने सुन रखा है कि आदिम जाति पहाड़िया के नाम पर सरकार करोड़ों राषि विभिन्न योजनाओं के लिए देती हैं। लिए जिला कल्याण विभाग तक वे पहुंची सारा और स्टेला षायद प्रतिनिधित्व कर हों उन जैसी और भी कई पहाड़िया व आदिम जनजाति समुदाय से आती ओं का, जो उच्च षिक्षा हासिल कर पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं। वे कुछ ीकी प्रषिक्षण भी लेना चाहती हैं। अपना न बेहतर बनाकर औरों के लिए भी कुछ का जज्बा रखती हैं लेकिन पहाड़िया ों के लिए हाईस्कूल तो हैं लेकिन उच्च के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। दोनों ओं ने जिला कल्याण पदाधिकारी को ा कि दोनों ने आठवीं के बाद सीधी क्ति के लिए भी फार्म भरा था लेकिन वहां उच्च षिक्षा प्राप्त उम्मीदवारों को मिकता पाता देख वे निराष हुई। फिर भी त न हारकर इंटर में प्रवेष ले लिया। हैं साल में एक बार दो हजार रूपये के लिए मिलता है। किताब-कॉपी, न में पैसे खर्च हो जाते हैं। परिवार आगे की षिक्षा व किसी तरह का प्रषिक्षण दिला पाने में असमर्थ है। इसलिए उन्होंने कल्याण विभाग की ओर रूख किया लेकिन वहां भी उन्हें टका सा जवाब मिला। अंत में मायूस होकर वे बोल पड़ी -कहने को करोड़ों रूपये आवंटित होते होंगे लेकिन देखिए कोई फायदा नहीं मिलता है हमें।

पहाड़ियाओं के लिए आवंटित राषि हुई लैप्स

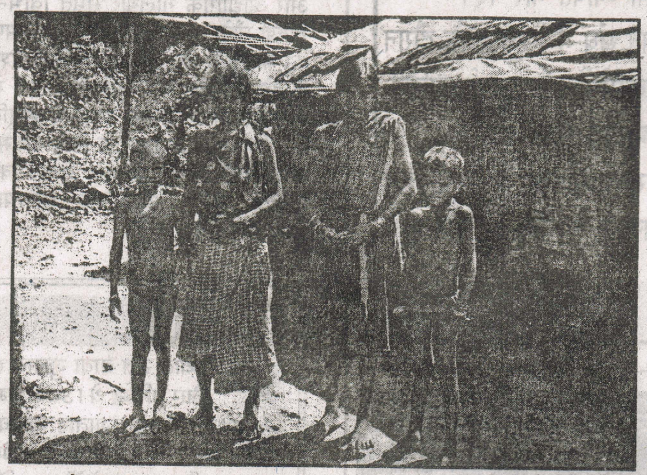

उधर दो पहाड़िया जागरूक छात्राएं कल्याण विभाग से मायूस होकर लौट रही थी और दूसरी ओर पहाड़ियाओं के लिए आवंटित राषि इसी साल लैप्स हो गई। समेकित जनजातीय विकास अभिकरण विभाग पहाड़ियाओं के आर्थिक, समाजिक, शैक्षणिक स्तर के उन्नयन के लिए काम करता है। इसके पूर्व निदेशक शिवजी चौपाल ने बताया कि वर्ष 2001-02 से लेकर वर्ष 2012-13 तक कुल 1317 पहाड़ियाओं को बिरसा आवास दिलाने का लक्ष्य था। इसमें विभाग ने 1170 योजनाएं ली, जिसमें मात्र 761 योजनाएं ही पूरी हुई है। कुल 230 योजनाएं पूरी नहीं हुई और इसकी करीब दो करोड़ तीस लाख की राशि लैप्स हो गई। कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि एक बिरसा आवास के लिए एक लाख रुपये की राशि आवंटित होती है। लेकिन इस राशि में बिरसा आवास नहीं बन पाता। इस राशि को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट इंप्लिमेंटेशन कमेटी को पत्र भेजा गया है और उन्होंने चालीस हजार की राशि बढ़ाने के लिए सरकार को पत्र लिखा है। इसी कारण वर्ष 2012-13 में कोई बिरसा आवास नहीं बन पाया और राशि वापस हो गई। आर्थिक विकास के लिए हार्टीकल्चर, रेशम का कोकून तैयार करने, वाटर हारवेस्टिंग, इरिगेशन एंड लैंड डेवलपमेंट के लिए सरकार काम कर रही है। इसमें रेशम के कोकून तैयार करने के लिए 2005-2008 में फेज-1 के तहत 578.20 करोड़ रूपया स्वीकृत हुआ। इसमें 468.86 करोड़ ही खर्च हो पाए और 63 लाख 27 हजार रूपये की राशि बची हुई है। एनजीओ के चयन न होने के कारण अब तक काम रूका हुआ है और राशि पड़ी हुई है। पूर्व डीसी ए.कुमार मुत्थु से पूछने पर कि सरकार ने उच्च षिक्षा की व्यवस्था पहाड़िया विद्यार्थियों के लिए नहीं की है फिर सीधी नियुक्ति के वक्त उच्च षिक्षा की मांग क्यों? सारा पहाड़िया व स्टेला पहाड़िया के साथ घटी घटना का जिक्र करने पर वे बस इतना ही कहते हैं इसमें थोड़ी समस्या है लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए।

साजिष के तहत पहाड़िया बाजार के बाहर

समाजिक कार्यकर्ता प्रेम हेम्ब्रोम बताते हैं कि यहां बाजार पर पूरी तरह साहूकारों का वर्चस्व है। पहाड़िया यदि कॉपरेटिव बना कर काम करना चाहें या अपनी चीजें बाजार में सीधे बेचना चाहे, तब भी वह सफल नहीं हो पाते। कारण यह है कि वे संगठित हो भी जाएं और अपनी चीजें जैसे बांस, बरबट्टी, लकड़ी बेचना चाहें, तब भी षडयंत्र के तहत उनकी चीजें कोई नहीं खरीदता है। थक-हार कर उन्हें बिचौलिया बने छोटे व्यापारियों के हाथों ही चीजें बेचनी पड़ती हैं। वह बताते हैं कि सरकारी पहल पर पहाड़ों पर लकड़ी डीपो खोलने का प्रयास किया गया था, जहां सारे पहाड़ियाओं की लकड़ियां जमा होती और वहीं से तय कीमत पर स्वयं पहाड़िया अपनी लकड़ियां बेचते। लेकिन साहूकारों की मिलीभगत के कारण व्यापारी उनके डीपो से लकड़ियां नहीं खरीदते थे। अंततः उन्हें बिचौलियों के हाथों अपनी लकड़ियां बेचने के लिए विवश होना पड़ा। कुछ वर्ष पहले सरकार ने पत्तल बनाने वाली मशीनें सभी पहाड़ों के पहाड़ियाओं को दिया था। इसके साथ उन्हें पत्तल बनाने का प्रशिक्षण भी दिया गया था। उनके द्वारा बनाए गए पत्तलों को इकट्ठा कर कोलकाता भेजा गया, लेकिन किसी भी व्यापारी ने उनके पत्तल नहीं खरीदे। बाद में गैर-पहाड़ियाओं ने बहला-फुसलाकर पहाड़ियाओं से सरकार द्वारा दी गयी पत्तल बनाने की मशीन खरीद ली और स्वयं पत्तल बनाने लगे। उनके द्वारा बनाये गये पतल ही आज बाजार में बिक रहे हैं। अब वे पहाड़ियो से पत्तल की जगह पत्ता खरीदते हैं और इसकी सबसे बड़ी मंडी बोरियो प्रखंड में है। वहां से हर दिन 3-4 ट्रक पत्ता बंगाल भेजा जाता है। जिले के पतना प्रखंड के सीतापहाड़ में रहकर कार्य करने वाले पुरोहित फा. पीए चाको ने पहाड़ियाओं पर किताब भी लिखी है। वे वकील भी हैं। वे कहते हैं पहाड़िया ग्राम सभा के नाम कॉपरेटिव बनाकर कुछ साल पहले लोगों द्वारा इमली स्थानीय बाजार के छोटे व्यापारियों को न बेचकर सीधे कोलकाता की मंडी तक पहुंचवाया गया। इमली ट्रक के ट्रक इलाहाबाद भेजा जाता था। सुबह से शाम हो गई। किसी भी व्यापारी ने उनकी चीजें नहीं खरीदी। इससे स्पष्ट अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरह षडयंत्र के तहत उन्हें बाजार से बाहर ही रखने की व्यवस्था की गई है। ताकि वे स्वयं अपनी चीजें चाहकर भी न बेच सके और साहूकारों का वर्चस्व बना रहे। इस प्रकार एक साजिष के तहत पहाड़ों के राजा कहलाने वाले पहाड़ियाओं को बाजार से बाहर रखा गया है ताकि पहाड़ों की उपज से वे अपनी आजीविका के साधन व अपनी स्थिति मजबूत न कर सके।

सीएसडीएस द्वारा प्रदत इनक्लूसिव मीडिया यूएनडीपी फेलोशिप के तहत रिपोर्टिंग।